<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ पर

<u>राष्ट्रीय अनुभव, आदान प्रदान कार्यक्रम</u>

24 फरवरी 2020, डॉ.अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की चौथी वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्तर का अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम डॉ.अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 24 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया । इस आयोजन की अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की।

इस आयोजन में 600 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और प्रेस के सदस्यों के के साथ-साथ क्लस्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन देश भर में क्लस्टर्स द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा तथा क्रिटिकल गैप फंडिंग के तहत प्रदान किए गए संसाधन उपयोग की जागरूकता और पैरवी करने के दोहरे उद्देश्य के साथ किया गया ।

कार्यक्रम की शुरुआत में संयुक्त सचिव, डॉ. बिस्वजीत बैनर्जी ने माननीय प्रधानमंत्री, के संदेश **“आत्मा गाँव की सुविधाओं शहर की”** संदेश का उल्लेख करते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। तमिलनाडु में सुत्तामल्लि क्लस्टर, मिजोरम में ऐबक क्लस्टर और उत्तर प्रदेश के पटेहरा कला क्लस्टर में निर्मित की जा रही जा रही विभिन्न आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के प्रदर्शन के लिए एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री ने 18 बिभिन्न राज्यों से संकलित 50 सफलता की कहानियों पुस्तक का विमोचन किया, जो इन जैविक विकास केंद्रों की आकांक्षाओं की झलक देती है।

माननीय मंत्री जी ने जियो रुर्बन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो मिशन के तहत किए गए कार्यों को तुरंत पंजीकृत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और क्लस्टर में किये गए कार्यों की प्रगति के भू-संदर्भित हस्ताक्षर के साथ लोगों के इंटरफेस की शुरुआत है।

अपने संबोधन के दौरान, माननीय मंत्री ने कहा कि रुर्बन (एसपीएमआरएम) एक **'भारतीय प्रयोग'** है जिसमें सहकारी संघवाद के माध्यम से ग्रामीण आकांक्षा को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायतो और स्वंय सहायता समूह के प्रतिनिधियों को अपने क्लस्टर विकास को व्यापक रूप से देखने के लिए प्रयास करना चाहिए और अंततः सभी योजनाओं के अभिसरण को लक्षित करना चाहिए। उन्होंने इस व्यापक विकास के दृष्टिकोण के लिए एसपीएमआरएम द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि हमें ग्रामीण भारत की वर्तमान चुनौतियों को अलग नजरिये के साथ अभिसरण तथा रोजगार के अवसरों के अनुकूल देखने की आवश्यकता है। जिससे, हम आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाले क्लस्टर्स के अंदर कई नए आजीविका विकल्प बना सकते हैं। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि, 288 क्लस्टर्स के विकास में मिशन के कार्यान्वयन से सीखने के साथ-साथ देश के चारो कोनो के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और राज्यों से मांग से, एक नया 1,000 क्लस्टर विकास कार्यक्रम जल्द ही शुरू हो सकता है।

माननीय राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने उदबोधन में कहा कि, रुर्बन मिशन के माध्यम से लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं और इसलिए कई विकास विकल्प संभव हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्लस्टर्स के विकास से हमारे शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण ने बताया कि, मिशन के प्रारम्भ होने के बाद से, 288 क्लस्टर्स की एकीकृत क्लस्टर विकास योजना विकसित की गई हैं और संबंधित राज्यों द्वारा 240 क्लस्टर्स की विस्तृत परियोजना

प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई है, जहां पहले से ही जमीनी स्तर पर विकास कार्य प्रारम्भ हो गए हैं। इन क्लस्टर्स में रु 28,075 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से रु 6,689 करोड़ रुपये के कार्य पहले ही किर्यान्वित हो चुके हैं। उन्होंने मिशन के माध्यम से हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर भी जोर दिया।

13 राज्यों के पंचायतो के प्रतिनिधियों, स्वंय सहायता समूह की महिलाओं और अधिकारियों ने अपने क्लस्टर विकास के अनुभवों का आदान प्रदान किया। जिला परिषद प्रकाशम जिले के सीईओ, श्री कैलाश गिरीश्वर ने रोजगार के विभिन्न विकल्पों की व्याख्या की और बताया कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। श्री मयूर दीक्षित, सीडीओ, उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड के साथ पंचायतो के प्रतिनिधिओं ने पहेनिया क्लस्टर में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास पर केंद्रित निवेश संगोष्ठी के आयोजन के बारे में बताया । उनके द्वारा निजी क्षेत्र के निवेश और कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) का समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में भी बताया गया । इसी प्रकार, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब के प्रतिनिधियों ने बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ क्लस्टर्स में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की प्रगति पर प्रदर्शन दिया।

इस आयोजन में श्री प्रशांत कुमार, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तथा अन्य मंत्रालयों से जैसे पंचायती राज मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।